न्यायमूर्ति परमजीत सिंह के समक्ष

लाडी -याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य

CRR No. 398 of 2013

02 मई 2013

भारतीय दंड संहिता, 1860 – धारा ***376, 506 - दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 -*** धारा, ***311 - भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 -*** धारा ***3 - सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000-*** उपधारा ***2, 4, और 7 - पीआईपी 17,8.2012 को धारा 3 76, 506 आई पीसी के तहत पंजीकृत किया गया था - मुकदमे के लंबित रहने के दौरान, तीन आवेदन दायर किए; (i) आरोपी ने अभियोजक की पुन: जांच के लिए (ii). आवाज का नमूना लेने के लिए; और (नमस्कार), सीडी के साथ पीड़िता की आवाज का नमूना परीक्षण के लिए भेजने के लिए - अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने आवेदन खारिज कर दिए - याचिकाकर्ता ने तीन पुनरीक्षण दायर किए - उपरोक्त सभी तीन आपराधिक पुनरीक्षण की अनुमति दी गई - याचिकाकर्ता/अभियुक्त के पास निष्पक्षता का एक अपरिहार्य अधिकार है अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए मुकदमा और समान अवसर - बचाव साक्ष्य प्रस्तुत करने का अभियुक्त का अधिकार न केवल एक औपचारिकता है, बल्कि आपराधिक मुकदमे का एक अनिवार्य हिस्सा है, जहां हर अवसर आवश्यक है और यह अभियुक्त को अपनी बेगुनाही साबित करने और बचाव पेश करने के लिए दिया जाना चाहिए।***

अभिनिर्धारित किया गया कि उपरोक्त प्रावधानों से यह स्पष्ट हो जाता है कि कानून। जैसा कि यह आज भी मौजूद है, लेक्स चुंबकीय या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पर संग्रहीत जानकारी की देखभाल करता है और इसे भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 के अर्थ में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में मानता है।

(पैरा 20)

इसके अलावा यह अभिनिर्धारित किया गया उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, स्थापित कानूनी प्रस्ताव यह है कि टेप रिकॉर्ड की गई बातचीत के प्राथमिक और प्रत्यक्ष साक्ष्य का उपयोग यह स्थापित करने के लिए किया जा सकता है कि किसी व्यक्ति ने किसी महत्वपूर्ण समय/अवसर पर क्या कहा था।

(पैरा 23)

इसके अलावा यह अभिनिर्धारित किया गया कि ,उपरोक्त के आलोक में, वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ता/अभियुक्त के पास निष्पक्ष सुनवाई और साबित करने के लिए समान अवसर का अपरिहार्य अधिकार है उसकी मासूमियत, यह स्थापित कानून है कि बचाव साक्ष्य पेश करने का आरोपी का अधिकार न केवल एक औपचारिकता है, बल्कि एक आपराधिक मुकदमे का एक अनिवार्य हिस्सा है, जहां हर अवसर आवश्यक है और यह आरोपी को अपनी बेगुनाही साबित करने और बचाव पेश करने के लिए दिया जाना चाहिए।

(पैरा 37)

इसके अलावा यह अभिनिर्धारित किया गया कि ,परिणामस्वरूप, याचिकाकर्ता द्वारा पीड़िता की दोबारा जांच करने, आवाज का नमूना लेने और सीडी के साथ पीड़िता की आवाज का नमूना प्रयोगशाला में भेजने के लिए दायर किए गए सभी तीन आवेदनों को अनुमति दी गई और विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, कैथल द्वारा दिनांक 16.01.2013 को पारित आदेश को अलग रखा गया है। ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिया गया है कि अभियोजक की केवल सेल फोन पर रिकॉर्ड की गई बातचीत के संबंध में पूछताछ की जाए और उसकी आवाज का नमूना लिया जाए और उसे वैज्ञानिक विश्लेषण के लिए भेजा जाए।

(पैरा 41)

याचिकाकर्ताओं की ओर से राकेश गुप्ता, वकील।

-संदीप एस मान, सीनियर डीएजी, मरियाना।

शिकायतकर्ता के वकील डी.आर.सिंगला।

न्यायमूर्ति परमजीत सिंह

(1) इस सामान्य आदेश द्वारा, आपराधिक पुनरीक्षण याचिकाएँ अर्थात। CRR No. 398 of 2013. CRR No. 399 of 2013 and CRR No. 400 of 2013 एक साथ तय किया जा रहा है क्योंकि यह मामला पुलिस स्टेशन गुहला, जिला कैथल में पंजीकृत एचआर नंबर 94, दिनांक 17.08.2012 से उत्पन्न हुआ है।

(2) 2013 की सीआरआर संख्या 398 को विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, कैथल द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.01.2013 के खिलाफ दायर किया गया है, जिसके तहत आपराधिक प्रक्रिया संहिता (इसके बाद "कोड" के रूप में संदर्भित) की धारा 311 के तहत पुन: आवेदन किया गया है। अभियोक्ता का परीक्षण खारिज कर दिया गया है।

(3) सीआरआर नंबर 400/2013 कैथल के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा पारित

आदेश दिनांक 16.01.2013 के खिलाफ दायर किया गया है, जिसके तहत पीड़िता की आवाज का नमूना लेने के आवेदन को अस्वीकार कर दिया गया है

(4) सीकेआर नंबर 399/2013 कैथल के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.01.2013 के खिलाफ दायर किया गया है, जिसके तहत परीक्षण के लिए सीडी के साथ पीड़िता की आवाज का नमूना भेजने के आवेदन को अस्वीकार कर दिया गया है।

(5) मामले के तीन तथ्य यह हैं कि एफआईआर संख्या 94 दिनांक 17.08.2012 है। याचिकाकर्ता के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376,506 के तहत पुलिस स्टेशन गुहला, जिला कैथल में मामला दर्ज किया गया था। एफआईआर में यह आरोप लगाया गया है कि 12.08.2012 को याचिकाकर्ता ने पीड़िता के साथ बलात्कार किया, जिसे दृढ़ता से नकार दिया गया है। यह आरोप लगाया गया है कि 11.08.2012 को अभियोजक और आरोपी-याचिकाकर्ता के बीच एक सेल फोन नंबर 96715-12799 से आरोपी-याचिकाकर्ता के सेल फोन नंबर 99928-56045 और 8295265454 पर बातचीत हुई थी। सेल फोन नंबर 96715-12799 श्री बलदेव सिंह के नाम पर है। आरोपी-याचिकाकर्ता के भाई के पास बातचीत रिकार्ड करने की सुविधा है। सेल फोन से, अभियुक्त और अभियोजन पक्ष के बीच बातचीत हुई और यह तथ्य श्री द्वारा अभियुक्त के संज्ञान में लाया गया। बाल्डसीवी सिंह दिनांक 04.01.2013. पहले यह आरोपी-याचिकाकर्ता की जानकारी में नहीं था। बातचीत से याचिकाकर्ता यह साबित करना चाहता है कि पीड़िता और आरोपी के बीच प्रेम संबंध था। उक्त बातचीत को सीडी में तब्दील कर दिया गया है, सीडी में अभियोक्ता की आवाज से उसका सामना कराने के उद्देश्य से, यह आवश्यक है कि अभियोक्ता से दोबारा पूछताछ की जाए, ताकि सीडी में दर्ज बातचीत से उसका आमना-सामना कराया जा सके।

(6) आवेदनों में यह भी प्रार्थना की गई है कि पीड़िता की आवाज का नमूना लिया जाए और उसका फोरेंसिक साइंस लैब से मिलान कराया जाए। तीनों आवेदनों को विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, कैथल द्वारा दिनांक 16.01.2013 के अलग-अलग आदेशों के तहत खारिज कर दिया गया है। तीन अलग-अलग आपराधिक पुनरीक्षणों में आक्षेप लगाया गया।

(7) विद्वान राज्य वकील ने मुख्य रूप से इस आधार पर उक्त आवेदनों का विरोध किया है कि ये सुनवाई योग्य नहीं हैं। आवेदन अस्पष्ट और गुण रहित हैं। भले ही आरोपी और पीड़िता के बीच सेल फोन पर बातचीत होती हो, लेकिन इससे पीड़िता को बलात्कार करने का लाइसेंस नहीं मिल जाता। यह है। हालाँकि, उन्होंने इस बात से इनकार किया कि आरोपी और अभियोजन पक्ष के बीच कोई बातचीत हुई है।

(8) मैंने उभय पक्षों के विद्वान वकीलों को सुना है और अभिलेख अवलोकन किया है

(9) सबसे पहले, मैं सूचना प्रौद्योगिकी युग के मद्देनजर कानून के साक्ष्य की अवधारणा पर विचार करना चाहूंगा जिसमें इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और कंप्यूटरों ने वस्तुतः हमारे जीवन पर कब्जा कर लिया है। साक्ष्य के कानून को लंबे समय से "सर्वोत्तम साक्ष्य" के नियम द्वारा

निर्देशित किया गया है, जिसे दो बुनियादी प्रतिमान माना जाता है, अफवाहों से बचना और प्राथमिक साक्ष्य का उत्पादन। 'FHC का मूल नियम यह है कि केवल प्रामाणिक साक्ष्यों पर ही विश्वास किया जाना चाहिए और प्रस्तुत किया जाना चाहिए जिन पर उचित रूप से संदेह नहीं किया जा सकता है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (इसके बाद "साक्ष्य अधिनियम" के रूप में संदर्भित) के अनुसार, एक व्यक्ति जिसने स्वयं यह महसूस किया हो (उसके तथ्य साबित हो रहे हों) इसके संबंध में गवाही दे सकता है, न कि तीसरा व्यक्ति, जिसने अभी जानकारी प्राप्त की है। इसी प्रकार , जहां किसी बात को साबित करने के लिए किसी दस्तावेज का उपयोग किया जाना है, वहां मूल को न्यायालय में प्रस्तुत किया जाना चाहिए, न कि प्रतिलिपि या फोटोग्राफ या कोई अन्य उत्पादन, सिवाय इसके कि जहां भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के प्रावधानों के तहत इसकी अनुमति हो। प्रौद्योगिकी के परिवर्तन के साथ, हर रोज साक्ष्य का नया रूप अस्तित्व में आ रहा है, पहले मोटे तौर पर मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य होते थे। प्रौद्योगिकी की प्रगति के साथ मौखिक साक्ष्य भी आ रहे हैं। मौखिक साक्ष्य को विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के माध्यम से भी दर्ज किया जा सकता है और उनसे तैयार किए गए उपकरणों का भी कई बार इलाज किया जा सकता है। दस्तावेज़ के रूप में। आजकल, रिकॉर्ड कैसेट, कॉम्पैक्ट डिस्क, पेनड्राइव, सीसीटीवी फुटेज पर तैयार किए जा रहे हैं, क्या इन्हें साक्ष्य अधिनियम के प्रावधानों के साथ-साथ निर्माण प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के प्रावधानों के अनुसार दस्तावेज़ माना जाना चाहिए (इसके बाद इसे "आईटी अधिनियम" कहा जाएगा)। 'इस प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को कंप्यूटर या अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के माध्यम से नियंत्रित और तैयार किया जाता है। रोजमर्रा की जिंदगी में प्रौद्योगिकी का बढ़ता उपयोग, विशेष रूप से इंटरनेट, सोशल साइट्स, सेल फोन कुछ उद्देश्यों के लिए उपयोगी हो सकते हैं और इसका उपयोग आपराधिक गतिविधियों के लिए भी किया जा सकता है। 'प्रौद्योगिकी के अपने फायदे और नुकसान हैं।

(10) इस विवादास्पद मुद्दे से निपटने से पहले कि क्या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में दर्ज की गई बातचीत "सीवीआईडीसीएनसीसी" की परिभाषा के अंतर्गत आती है, साक्ष्य अधिनियम और आईटी अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों को पुन: प्रस्तुत करना उचित होगा: -

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872

3. व्याख्या उपवाक्य. - इस अधिनियम में निम्नलिखित शब्दों और अभिव्यक्तियों का उपयोग निम्नलिखित अर्थों में किया जाता है, जब तक कि संदर्भ से कोई विपरीत इरादा प्रकट न हो:-

"दस्तावेज़" -"दस्तावेज़" का अर्थ किसी पदार्थ पर अक्षरों, अंकों या चिह्नों के माध्यम से या उनमें से एक से अधिक माध्यमों द्वारा व्यक्त या वर्णित कोई भी मामला है, जिसका उद्देश्य उस मामले को रिकॉर्ड करने के लिए उपयोग किया जा सकता है, या जिसका उपयोग किया जा सकता है।

"प्रमाण" -"साक्ष्य" का अर्थ है और इसमें शामिल है -

(1) जांच के अधीन मामलों के संबंध में सभी बयान जो न्यायालय गवाहों द्वारा उसके समक्ष दिए जाने की अनुमति देता है या अपेक्षित करता है; ऐसे कथनों को मौखिक साक्ष्य कहा जाता है;

(2) न्यायालय के निरीक्षण के लिए प्रस्तुत किए गए इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड सहित सभी दस्तावेज, ऐसे दस्तावेजों को दस्तावेजी साक्ष्य कहा जाता है।

'प्रारूप आयन प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000

2. परिभाषाएँ -(1) इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -

XXXX XXXX XXX XXX

(एचए) "संचार उपकरण" का अर्थ है सेल फोन, व्यक्तिगत डिजिटल सहायता या दोनों का संयोजन या कोई अन्य उपकरण जो किसी भी पाठ, वीडियो, ऑडियो या छवि को संचारित करने, भेजने या प्रसारित करने के लिए उपयोग किया जाता है;

(i) "कंप्यूटर" का अर्थ है कोई भी इलेक्ट्रॉनिक, चुंबकीय, ऑप्टिकल या अन्य उच्च गति डेटा प्रोसेसिंग उपकरण या सिस्टम जो इलेक्ट्रॉनिक, चुंबकीय या ऑप्टिकल आवेगों के हेरफेर द्वारा तार्किक, अंकगणित और मेमोरी कार्य करता है, और इसमें सभी इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग, स्टोरेज, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर या शामिल हैं। संचार सुविधाएं जो किसी कंप्यूटर सिस्टम या कंप्यूटर नेटवर्क में कंप्यूटर से जुड़ी या संबंधित हैं;

(j) "कंप्यूटर नेटवर्क" का अर्थ है कंप्यूटर या कंप्यूटर सिस्टम या संचार उपकरण का अंतर-कनेक्शन -

(i) उपग्रह, माइक्रोवेव, स्थलीय लाइन, तार, वायरलेस या अन्य संचार मीडिया का उपयोग; और

(ii) टर्मिनल या एक कॉम्प्लेक्स जिसमें दो या दो से अधिक परस्पर जुड़े हुए कंप्यूटर या संचार उपकरण हों, चाहे अंतर-संबंध निरंतर बना रहे या नहीं;

(o) "डेटा" का अर्थ है जानकारी, ज्ञान, संधियों, अवधारणाओं या निर्देशों का प्रतिनिधित्व जो औपचारिक तरीके से तैयार किया जा रहा है या तैयार किया गया है, और संसाधित होने का इरादा है, संसाधित किया जा रहा है या कंप्यूटर सिस्टम या कंप्यूटर नेटवर्क में संसाधित किया गया है , और किसी भी रूप में हो सकता है (कंप्यूटर प्रिंटआउट चुंबकीय या ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया, छिद्रित कार्ड, छिद्रित टेप सहित) या कंप्यूटर की मेमोरी में आंतरिक रूप से संग्रहीत;

XXXXXX XXX XXX

(r) सूचना के संदर्भ में, "इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म" का अर्थ मीडिया, चुंबकीय, ऑप्टिकल, कंप्यूटर

मेमोरी, माइक्रो फिल्म, कंप्यूटर जनित माइक्रो फाई सी या समान डिवाइस में उत्पन्न, भेजी, प्राप्त या संग्रहीत कोई भी जानकारी है;

(s) "हेल्क्रोनिक गजट" का अर्थ इलेक्ट्रॉनिक फोन में प्रकाशित आधिकारिक राजपत्र है;

(t) "इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड" का अर्थ है इलेक्ट्रॉनिक फोन या माइक्रो फिल्म या कंप्यूटर जनित माइक्रो फिच में डेटा, रिकॉर्ड या उत्पन्न डेटा, संग्रहीत, प्राप्त या भेजी गई छवि या ध्वनि;

XXXXXX XXX

(v) "सूचना" में डेटा, संदेश, पाठ, चित्र, ध्वनि, आवाज, कोड, कंप्यूटर प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर और डेटाबेस या माइक्रो फिल्म या कंप्यूटर जनित माइक्रो फिच शामिल हैं;

XXXXXX XXX

4. **इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की कानूनी मान्यता -**जहां कोई भी कानून यह प्रावधान करता है कि सूचना या कोई अन्य मामला लिखित या टंकित या मुद्रित रूप में होगा, तो ऐसे कानून में किसी भी बात के बावजूद, ऐसी आवश्यकता को संतुष्ट माना जाएगा यदि ऐसी जानकारी या मामला -

(a) इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रस्तुत या उपलब्ध कराया गया; और

(b) पहुंच योग्य ताकि बाद के संदर्भ के लिए उपयोग किया जा सके।

7. **इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का रखरखाव**-(1) जहां कोई भी कानून यह प्रावधान करता है कि दस्तावेज़, रिकॉर्ड या सूचना किसी के विशेष अवधि लिए भी रखी जाएगी, तो, उस आवश्यकता को संतुष्ट माना जाएगा यदि ऐसे दस्तावेज़, रिकॉर्ड या जानकारी इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखी जाती है, यदि-

(a) उसमें मौजूद जानकारी सुलभ रहती है ताकि बाद के संदर्भ के लिए उपयोग योग्य हो सके;

(b) इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को उसी प्रारूप में रखा जाता है जिसमें वह मूल रूप से उत्पन्न, भेजा या प्राप्त किया गया था या ऐसे प्रारूप में जिसे मूल रूप से उत्पन्न, भेजी या प्राप्त की गई जानकारी को सटीक रूप से प्रदर्शित करने के लिए प्रदर्शित किया जा सके;

(c) विवरण जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में उपलब्ध ऐसे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड आर्क की उत्पत्ति, गंतव्य, प्रेषण की तारीख और समय की पहचान की सुविधा प्रदान करेगा:

बशर्ते कि यह खंड किसी भी ऐसी जानकारी पर लागू नहीं होता है जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को भेजने या प्राप्त करने में सक्षम बनाने के उद्देश्य से स्वचालित रूप से उत्पन्न होती है।

(2) इस धारा की कोई भी बात किसी ऐसे कानून पर लागू नहीं होगी जो स्पष्ट रूप से दस्तावेजों, अभिलेखों को बनाए रखने या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के रूप में बनाने का प्रावधान करता है।

(11) आईटी एक्ट में संशोधन और आने से पहले साक्ष्य अधिनियम मुख्य रूप से उन साक्ष्यों से संबंधित था जो मौखिक या दस्तावेजी रूप में थे। विद्युत-चुंबकीय उपकरण में दर्ज की गई बातचीत या बयान की स्वीकार्यता, प्रकृति और साक्ष्य मूल्य के बारे में कुछ भी नहीं था। अब, दान प्रौद्योगिकी में प्रौद्योगिकी और परिष्कार की प्रगति के साथ, साक्ष्य एकत्र करने और संरक्षित करने के लिए अदालतों और जांच एजेंसियों के सामने विभिन्न चुनौतियां आ रही हैं। यह साक्ष्य की गुणवत्ता है जो दोषसिद्धि या सजा के उद्देश्य के लिए प्रासंगिक है। आपराधिक आसानी से बरी होना। सूचना प्रौद्योगिकी के आगमन ने एक नए प्रकार के दस्तावेज़ को अस्तित्व में लाया है जिसे "इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड" कहा जाता है। नए प्रकार के इस अमूर्त दस्तावेज़ में दस्तावेज़ों के पारंपरिक रूप की तुलना में कुछ विशिष्टता है। ऐसे दस्तावेज़ों को संरक्षित किया जा सकता है एन्क्रिप्शन प्रक्रियाओं के माध्यम से लंबी अवधि तक समान गुणवत्ता और स्थिति से साक्ष्यों से छेड़छाड़ की संभावना कम हो जाती है।

(12) 'कानून और प्रौद्योगिकी के बीच संबंध हमेशा आसान नहीं रहा है। '1'एचसी कानून हमेशा जब भी आवश्यक पाया गया है, प्रौद्योगिकी के पक्ष में खड़ा हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक रूप से रिकॉर्ड की गई बातचीत की उपयोगिता और स्वीकार्यता के संबंध में कानून अदालतों की चिंता समय-समय पर विभिन्न घोषणाओं में व्यक्त होती रही है। कार्लिकस्ट आसानी जिसमें टेप-रिकॉर्ड की गई बातचीत की स्वीकार्यता का मुद्दा विचार के लिए आया, वह हूप चंद बनाम महाबीर प्रसाद (1) है। इस सहजता में न्यायालय ने हालांकि टेप-रिकॉर्ड की गई बातचीत को धारा 3 (65) के अर्थ के तहत लेखन के रूप में मानने से इनकार कर दिया, लेकिन साक्ष्य अधिनियम की धारा 155 (3) के

तहत इसे हिलाने के लिए पिछले बयान के रूप में उपयोग करने की अनुमति दी। साक्षी का श्रेय न्यायालय ने माना कि साक्ष्य का कोई नियम नहीं है, जो एक पक्ष को, जो पूर्व असंगत बयान का उपयोग करके गवाह की साख को हिलाने का प्रयास कर रहा है, को गवाही देने से रोकता है कि जब वह गवाह के साथ बातचीत में लगा हुआ था, तो एक टेप रिकॉर्डर था संचालन में है, या इस दावे के समर्थन में उक्त टेप रिकॉर्डर का उत्पादन कर रहा है कि बयान उसकी उपस्थिति में दिया गया था।

(13) 5. प्रताप सिंह बनाम पंजाब राज्य (2) में, । लोन'ब्लक सुप्रीम कोर्ट की एक न्यायाधीशों की खंडपीठ ने इस मुद्दे पर विचार किया और स्पष्ट रूप से प्रतिपादित किया कि टेप रिकॉर्ड की गई बातचीत साक्ष्य और साधारण तथ्य में स्वीकार्य है कि इस प्रकार की बातचीत आसानी से की जा सकती है। छेड़छाड़ की गई जो निश्चित रूप से ऐसे सबूतों को अस्वीकार्य मानकर खारिज करने का आधार नहीं हो सकता। संभवतः ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है, जिसके साथ छेड़छाड़ न की जा सके। इस सहजता में उन गवाहों के सबूतों की पुष्टि के लिए टेप रिकॉर्ड की गई बातचीत को साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया गया, जिन्होंने कहा था कि ऐसी बातचीत हुई थी।

(14) यूसुफ अली इस्माइल पीएल सहमत बनाम महाराष्ट्र राज्य (3) मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता की धारा 165-ए के तहत टेप रिकॉर्ड की गई बातचीत की स्वीकार्यता के मुद्दे पर विचार किया। आरोपी, जो रिश्वत देना चाहता था, और शिकायतकर्ता के बीच टेप रिकॉर्ड किया गया था। 'अभियोजन पक्ष इस टेप रिकॉर्ड की गई बातचीत को आरोपी के खिलाफ सबूत के रूप में इस्तेमाल करना चाहता था। इसका इस आधार पर विरोध किया गया कि यह सीआरपीसी की धारा 162 के साथ-साथ अनुच्छेद से भी प्रभावित है। संविधान के अनुच्छेद 20(3)इसमें निर्णय में, प्रथम सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि टेप रिकॉर्डिंग की प्रक्रिया ध्वनि को संग्रहीत करने और बाद में पुन: प्रस्तुत करने की एक सटीक विधि है। चुंबकीय टैपसीस पर छाप संबंधित ध्वनियों का सीधा प्रभाव डालती है, जैसे किसी प्रासंगिक घटना की तस्वीर। प्रासंगिक बातचीत की समसामयिक टेप रिकॉर्डिंग एक प्रासंगिक तथ्य है और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 7 के तहत स्वीकार्य है। प्रथम लोक उच्चतम न्यायालय ने पूरे मुद्दे की जांच के बाद विभिन्न घोषणाओं के आलोक में निम्नानुसार जांच की: -

(a) यानी समसामयिक संवाद, जो टेप रिकॉर्ड किया गया था, आरसीएस-जीसीएसटीएके का हिस्सा है और भारतीय कानून अधिनियम की धारा 8 के तहत प्रासंगिक और स्वीकार्य है।

(b) प्रासंगिक बातचीत का समसामयिक टेप रिकॉर्ड एक प्रासंगिक तथ्य है और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 7 के तहत स्वीकार्य है।

(c) ऐसा बयान वास्तव में जांच के दौरान पुलिस को दिया गया बयान नहीं था और इसलिए, इसे आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 162 के तहत अस्वीकार्य नहीं माना जा सकता है।

(d) इस तरह की रिकॉर्ड की गई बातचीत हालांकि आरोपी की जानकारी के बिना हासिल की गई है, लेकिन इसे दबाव, दबाव या दबाव से नहीं लिया गया है और न ही दमनकारी तरीके से या बलपूर्वक या आरोपी की इच्छा के खिलाफ निकाला गया है। इसलिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 20(3) का संरक्षण उपलब्ध नहीं था।

(c) चुंबकीय टेप रिकॉर्डिंग की एक विशेषता रिकॉर्डिंग माध्यम को मिटाने और पुन: उपयोग करने की क्षमता है। इसलिए, साक्ष्य सावधानी से प्राप्त किया जाना चाहिए। न्यायालय को उचित संदेह से परे संतुष्ट होना चाहिए कि रिकॉर्ड के साथ छेड़छाड़ नहीं की गई है।

(15) यह जोरदार तर्क दिया गया है कि टेप में रिकॉर्ड की गई बातचीत को बाद की रिकॉर्डिंग द्वारा आसानी से मिटाया जा सकता है और सम्मिलन को आरोपित किया जा सकता है। 11 वास्तव में, इस कारक का साक्ष्य के साथ संलग्न किए जाने वाले महत्व पर प्रभाव पड़ेगा, न कि उसकी स्वीकार्यता पर। अंततः, यदि अदालत को संदेह है कि टेप रिकॉर्डिंग के साथ छेड़छाड़ की गई है तो यह अदालत के लिए इसके साक्ष्य मूल्य को पूरी तरह से खारिज करने का एक अच्छा आधार होगा।

प्रताप सिंह बनाम पंजाब राज्य (सुप्रा) में देखा गया। राम सिंह बनाम सीओएल राम सिंह (4) के मामले में, टेप रिकॉर्ड की गई बातचीत की स्वीकार्यता के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा निम्नलिखित दिशानिर्देश निर्धारित किए गए थे:

(1) 'यानि वक्ता की आवाज को रिकॉर्ड बनाने वाले या उसकी आवाज पहचानने वाले अन्य लोगों द्वारा विधिवत पहचाना जाना चाहिए। जहां निर्माता ने आवाज से इनकार किया है, वहां यह निर्धारित करने के लिए बहुत सख्त सबूत की आवश्यकता होगी कि यह वास्तव में वक्ता की आवाज थी या नहीं।

(2) टेप रिकॉर्ड किए गए बयान की सटीकता को रिकॉर्ड के निर्माता द्वारा प्रत्यक्ष या परिस्थितिजन्य संतोषजनक साक्ष्य द्वारा साबित करना होगा।

(3) टेप रिकॉर्ड किए गए बयान के एक हिस्से के साथ छेड़छाड़ या उसे मिटाने की संभावना को खारिज किया जाना चाहिए अन्यथा यह उक्त बयान को संदर्भ से बाहर कर सकता है और इसलिए, अस्वीकार्य हो सकता है।

(4) कथन 1 साक्ष्य अधिनियम के नियमों के अनुसार प्रासंगिक होना चाहिए।

(5) रिकॉर्ड किए गए कैसेट को सावधानीपूर्वक सील किया जाना चाहिए और सुरक्षित या आधिकारिक हिरासत में रखा जाना चाहिए।

(6) वक्ता की आवाज स्पष्ट रूप से सुनाई देने योग्य होनी चाहिए और अन्य ध्वनियों

या व्यवधान से लुप्त या विकृत नहीं होनी चाहिए।

(16) 'यह महत्वपूर्ण प्रश्न टेप की गई आवाज की पहचान के संबंध में है। ऐसी टेप रिकॉर्डिंग के उपयोग के लिए ऐसी आवाज की उचित पहचान एक अनिवार्य शर्त है, इसलिए, रिकॉर्डिंग का समय, स्थान और सटीकता एक सक्षम गवाह द्वारा साबित की जानी चाहिए और आवाज की उचित पहचान होनी चाहिए।

(17) टेप-रिकॉर्ड की गई बातचीत की प्रतिलेख रखने के महत्व को कम करके नहीं आंका जा सकता क्योंकि यह सुनिश्चित करता है कि रिकॉर्डिंग के साथ बाद में छेड़छाड़ नहीं की गई थी। (ज़ियाउद्दीन बुरहानुद्दीन बुखारी बनाम बृजमोहन रामदास मेहता (5) मामले में, प्रथम लोक सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी प्रतिलेख के मूल्य और उपयोग पर विचार किया है और विचार व्यक्त किया है कि प्रतिलेख निश्चित रूप से पुष्टिकारक है। यह पुष्टि करने के लिए जाता है कि टेप रिकॉर्ड में क्या था। 11 'बायो' पर सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि इस तरह के प्रतिलेखों का उपयोग गवाह द्वारा धारा के तहत अपनी याददाश्त को ताज़ा करने के लिए किया जा सकता है! साक्ष्य अधिनियम की धारा 59 और उनकी सामग्री को साक्ष्य अधिनियम की धारा 160 द्वारा निर्धारित तरीके से प्रत्यक्ष मौखिक साक्ष्य द्वारा रिकॉर्ड पर लाया जा सकता है।

(18) ' टेप-आरसीओआरडीसीडी बातचीत एक चुंबकीय मीडिया पर संग्रहीत जानकारी के अलावा और कुछ नहीं है। हालाँकि, रूप चंद (सुप्रा) की सहजता में, इस न्यायालय ने जनरल क्लॉज एक्ट की धारा 3 (65) के अर्थ के भीतर टेप रिकॉर्ड की गई बातचीत को एक लेखन के रूप में मानने से इनकार कर दिया, ज़ियादीन बुरहानुद्दीन बुखारी में 1 लोन्ब्लक सुप्रीम कोर्ट (सुप्रा) ने स्पष्ट रूप से निर्धारित किया कि टेप रिकॉर्ड किए गए भाषण साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 द्वारा परिभाषित "दस्तावेज" थे, जो तस्वीरों से अलग नहीं थे।

(19) इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, 2000 (w.c.f. 17.10.2000) के लागू होने से साक्ष्य की पारंपरिक अवधारणा पूरी तरह से सुधर गई है। इस अधिनियम की धारा 2 (आर) इस संबंध में प्रासंगिक है जो "इलेक्ट्रॉनिक रूप" में जानकारी को मीडिया, चुंबकीय, ऑप्टिकल, कंप्यूटर मेमोरी, माइक्रो फिल्म, कंप्यूटर जनित माइक्रो फिच या इसी तरह के डिवाइस में उत्पन्न, भेजी, प्राप्त या संग्रहीत जानकारी के रूप में परिभाषित करती है। इस अधिनियम की धारा 2 (टी) "इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड" का अर्थ है डेटा, रिकॉर्ड या उत्पन्न डेटा, संग्रहीत छवि या ध्वनि, इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्राप्त या भेजा गया या माइक्रो फिल्म या कंप्यूटर जनित माइक्रो फिच। Schcdulc(2) के साथ पठित आईटी अधिनियम की धारा 92 ने भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 में निहित 'साक्ष्य' की परिभाषा में संशोधन किया। संशोधित परिभाषा इस प्रकार है:

"साक्ष्य:- 'साक्ष्य' का अर्थ है और इसमें शामिल है-

(1) जांच के तहत तथ्य के मामलों के संबंध में सभी बयान जिन्हें अदालत गवाह द्वारा उसके समक्ष बीसीएमएडीसी करने की अनुमति देती है या आवश्यकता होती है; ऐसे कथन को मौखिक साक्ष्य कहा जाता है:

(2) न्यायालय के निरीक्षण के लिए प्रस्तुत इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड सहित सभी दस्तावेज़; ऐसे दस्तावेजों को दस्तावेजी साक्ष्य कहा जाता है।"

(20) उपरोक्त प्रावधानों से यह स्पष्ट हो जाता है कि कानून, जैसा कि आज मौजूद है, चुंबकीय या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पर संग्रहीत जानकारी का ख्याल रखता है और इसे भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 के अर्थ में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में मानता है।

(21) अगला प्रश्न टैपसी-पुनर्व्यवस्थित जानकारी की उपयोगिता और साक्ष्य मूल्य के बारे में है, उपयोगिता और साक्ष्य मूल्य के बारे में है। इस संबंध में निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार आवश्यक है:

(a) क्या ऐसा साक्ष्य प्राथमिक या द्वितीयक है?

(b) क्या ऐसा साक्ष्य प्रत्यक्ष है या अफवाह है?

(e) क्या ऐसे साक्ष्य पुष्टिकारक या ठोस हैं?

(22) 'इस बिंदु पर कि क्या ऐसा साक्ष्य प्राथमिक और प्रत्यक्ष है, इस पर 11 'बी यानी सुप्रीम कोर्ट/वी' द्वारा विचार किया गया था। श्री राम रेड्डी बनाम केके गिरी (6)। सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि किसी भी दस्तावेज़ की तरह टेप रिकॉर्ड स्वयं प्राथमिक और प्रत्यक्ष साक्ष्य है जो रिसीवर द्वारा कही गई और उठाई गई बातों के लिए स्वीकार्य है। इस विचार को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र राज्य (7) के आरके मटकाएवेरक्सस मामले में दोहराया था। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि जब कोई अदालत किसी टेप रिकॉर्डिंग को चलाने की अनुमति देती है तो वह वास्तविक साक्ष्य पर काम कर रही है यदि वह शब्दों के स्वर को प्रासंगिक और वास्तविक मानती है। रामा रेड्डी के मामले (सुप्रा) में निर्धारित कानून के प्रस्ताव का उल्लेख करते हुए, सुप्रीम कोर्ट के तीन न्यायाधीशों की पीठ ने वाज़ियाउद्दीन रत्तरहाऊउद्दीन रुखारी (सुप्रा) में प्रतिपादित किया कि टेप रिकॉर्ड की गई बातचीत का उपयोग उद्देश्य तक ही सीमित नहीं था। केवल पुष्टि और विरोधाभास का, लेकिन जब जो दर्ज किया गया था उसके संतोषजनक साक्ष्य द्वारा विधिवत साबित किया जाता है और छेड़छाड़ की अनुपस्थिति होती है, तो इसे साक्ष्य अधिनियम के प्रावधानों के अधीन, मूल साक्ष्य के रूप में उपयोग किया जा सकता है। एक उदाहरण देते हुए, न्यायालय ने बताया कि जब यह विवादित था या किसी विशेष अवसर पर किसी व्यक्ति के भाषण में एक विशेष बयान शामिल था, तो इसकी प्रामाणिकता मानते हुए इसके टेप रिकॉर्ड से अधिक प्रत्यक्ष या बेहतर सबूत नहीं हो सकता था। विधिवत स्थापित.

(23) उपरोक्त यूने के विचार में, स्थापित कानूनी प्रस्ताव यह है कि टेप रिकॉर्ड की गई बातचीत के प्राथमिक और प्रत्यक्ष होने के साक्ष्य का उपयोग यह स्थापित करने के लिए किया जा सकता है कि किसी व्यक्ति ने किसी महत्वपूर्ण समय/अवसर पर क्या कहा था।

(24) भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 157 के तहत, एक गवाह की पुष्टि उसके

पिछले बयान से की जा सकती है। अधिनियम की धारा 145 (6) एआईआर 1971 एससी 1162 (7) एआईआर 1973 एससी 157 के दौरान गवाह के विरोधाभास के लिए पिछले बयान के उपयोग की अनुमति देती है।

फिर से धारा 146 के खंड (l) में यह प्रावधान है कि जिरह के दौरान, किसी गवाह से उसकी सत्यता का परीक्षण करने के लिए प्रश्न पूछे जा सकते हैं। धारा 153 आम तौर पर सत्यता का परीक्षण करने वाले प्रश्नों के उत्तरों का खंडन करने वाले सबूतों के बहिष्कार से संबंधित है, मैं कम कहता हूं, इसका अपवाद (2) यह है कि एक गवाह का खंडन किया जा रहा है यदि उसने किसी भी तथ्य से इनकार कर दिया है जो उसकी निष्पक्षता पर सवाल उठाने के लिए उसके सामने रखा गया था। धारा 155 (3) एक गवाह के साक्ष्य के किसी भी हिस्से के साथ असंगत पूर्व बयानों के सबूत के आधार पर उसके विश्वास को दोषी ठहराने से संबंधित है, जिसका खंडन किया जा सकता है।

(25) 'एसीवीआर/कामा केडी (सुप्रा) में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर विचार करने के बाद यह निर्धारित किया कि टेप रिकॉर्ड की गई बातचीत/स्टेटसीएमसीएनटी के सबूत पुष्टि के लिए इस्तेमाल किए जाने के अलावा धारा 146 (1) में बताए गए उद्देश्यों के लिए स्वीकार्य हैं। साक्ष्य अधिनियम की धारा 1 53 और धारा 155 (3) का अपवाद (2)।

(26) 'इस मामले पर राज्य बनाम नवजोत संधू (8) मामले में एकल सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी विचार किया गया था।

(27) 'विद्वान ट्रायल कोर्ट ने अभियोजक की दोबारा जांच के लिए इली कोड की धारा 311 के तहत आवेदन को खारिज करते हुए कहा है कि:-

> "...अभियोक्ता का बयान 5.11.2012 को दर्ज किया गया था और उसकी लंबी जिरह की गई है जो लगभग छह पृष्ठों में है और हर पहलू पर उससे जिरह की गई है। मुकदमे के एक निष्कर्ष के अनुसार, आरोपी-आवेदक ने बचाव साक्ष्य का नेतृत्व करने और तर्कों को आगे बढ़ाने के लिए चार प्रभावी अवसरों का भी लाभ उठाया है। एक बार, सभी भौतिक पहलुओं पर अभियोक्ता की जिरह दर्ज कर ली गई है और जहां तक अभियोक्ता का बयान दर्ज करने का सवाल है, अदालत को काफी सतर्क रहना होगा और अन्यथा भी, गवाह को वापस बुलाना कोई नियमित मामला नहीं है, बल्कि विवेक का प्रयोग बहुत संयमित ढंग से और दुर्लभ सहजताओं के बीच किया जाना चाहिए। एक बार जब यह रिकॉर्ड की बात हो जाती है कि अभियोक्त्री से सभी भौतिक पहलुओं पर विस्तार से जिरह की जा चुकी है, तो अभियोक्ता को उसकी आगे की जिरह रिकॉर्ड करने के लिए वापस बुलाने का कोई अवसर नहीं है और ऐसा प्रतीत होता है कि चूंकि अभियोक्ता से पहले ही जिरह हो चुकी है। निष्कर्ष निकाला गया, वर्तमान आवेदन और कुछ नहीं बल्कि कार्यवाही को लम्बा खींचने के लिए कानून की प्रक्रिया के साथ-साथ अदालत का दुरुपयोग है..."

(28) वर्तमान सहजता में, अभियोजक की आवाज का नमूना लेने और उसकी प्रामाणिकता की जांच और सत्यापन के लिए सीडी के साथ अधिकृत सरकारी प्रयोगशाला में भेजने के आवेदन को भी खारिज कर दिया गया है।

(29) यह शिकायतकर्ता/अभियोजक के लिए आसानी थी कि जब अदालत में उसका बयान दर्ज किया जा रहा था तो उसके और याचिकाकर्ता के बीच कथित टेप रिकॉर्ड की गई बातचीत के बारे में उससे कभी जिरह नहीं की गई।

(30) आगे बढ़ने से पहले, रिकॉर्ड की गई बातचीत की स्वीकार्यता और पक्षों की आवाज के नमूने लेने की अनुमति देने पर विचार करना प्रासंगिक होगा। 1956 की शुरुआत में, हूप चंद के मामले में यह स्पष्ट रूप से माना गया था कि गवाह के पूर्व बयान का टेप रिकॉर्ड किया गया संस्करण गवाह की विश्वसनीयता को हिला देने के लिए साक्ष्य में स्वीकार्य है। प्रियाप सिंह मामले में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि बातचीत का टेप रिकॉर्ड किया गया संस्करण उस गवाह के साक्ष्य की पुष्टि करने के लिए साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य था जिसने कहा था कि ऐसी बातचीत हुई थी।

(31) केएम मलकानी बनाम महाराष्ट्र के राज्य (9) में, सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार टिप्पणी की है:

> “23. टेप रिकॉर्ड की गई बातचीत स्वीकार्य है, बशर्ते कि बातचीत संबंधित मामलों से प्रासंगिक हो; दूसरे, आवाज की पहचान होती है; और, तीसरा, टेप-रिकॉर्ड को मिटाने की संभावना को समाप्त करके टेप रिकॉर्ड की गई बातचीत की सटीकता साबित होती है। किसी प्रासंगिक बातचीत का समसामयिक टेप-रिकॉर्ड एक प्रासंगिक तथ्य है और साक्ष्य अधिनियम की धारा 8 के तहत स्वीकार्य है। यह रेस गेस्टे है
>
> xxxxxxxxxxxx

29. यह कहा गया था कि टेप रिकॉर्ड किए गए साक्ष्य की स्वीकार्यता ने कला को नाराज कर दिया। संविधान के अनुच्छेद 20(3) और 21 दलील यह थी कि टेप रिकॉर्ड की गई बातचीत को प्राप्त करने का तरीका कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया नहीं थी और अपीलकर्ता (9) एआईआर 1973 एससी 157 था।

> दोषी ठहराया गया। अपीलकर्ता की बातचीत स्वैच्छिक थी। 'यहां कोई जबरदस्ती नहीं थी, टेप रिकॉर्डिंग उपकरण संलग्न करने के बारे में अपीलकर्ता को जानकारी नहीं थी। यह तथ्य बातचीत के साक्ष्य को अस्वीकार्य नहीं बनाता है। अपीलकर्ता की बातचीत दबाव या मजबूरी के तहत नहीं ली गई थी। यदि बातचीत टेप पर रिकॉर्ड की गई थी तो यह सुनने वाले की भूमिका निभाने के लिए एक यांत्रिक युक्ति थी। आर वी. लैथम, (1861) 8 कॉक्स सीसी 198 में यह कहा गया था, "यह मायने नहीं रखता कि आप इसे कैसे प्राप्त करते हैं यदि आप इसे चुराते हैं, भले ही यह साक्ष्य में स्वीकार्य होगा" जब तक कि यह

अपराध की अस्वीकार्य स्वीकारोक्ति से दूषित न हो; साक्ष्य भले ही अवैध रूप से प्राप्त किया गया हो, स्वीकार्य है।"

(32) मैंने केके वेलुसामी बनाम/वी मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की। पामुक्सामी (10) ने टेलीफोनिक बातचीत की रिकॉर्डिंग के बारे में विचार किया और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि टेलीफोनिक बातचीत की रिकॉर्डिंग वाली डिस्क भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 3 और आईटी अधिनियम की धारा 2 (टी) के अनुसार एक वैध साक्ष्य हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इलेक्ट्रॉनिक रूप से रिकॉर्ड की गई बातचीत साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य है, यदि बातचीत मुद्दे के स्तर से संबंधित है और आवाज की पहचान की गई है और मिटाए जाने की संभावना को समाप्त करके रिकॉर्ड की गई बातचीत की सटीकता साबित की गई है। , जोड़ या हेरफेर। 'निर्णय का प्रासंगिक पैरा निम्नानुसार पुन: प्रस्तुत किया गया है:

> “7. साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 3 में "साक्ष्य" की संशोधित परिभाषा। को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 2(टी) में " इलेक्ट्रोनिक रिकॉर्ड" की परिभाषा के साथ पढ़ा जाता है। इसमें एक कॉम्पैक्ट डिस्क शामिल है जिसमें बातचीत का इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड होता है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 8 में यह प्रावधान है कि किसी भी मुकदमे के संदर्भ में किसी भी पक्ष या किसी भी पक्ष के एजेंट का आचरण, ऐसे मुकदमे के संदर्भ में, या उसमें मुद्दे के किसी भी तथ्य के संदर्भ में या उससे संबंधित, प्रासंगिक है, यदि ऐसा आचरण प्रभावित करता है या किसी विवादित तथ्य या प्रासंगिक तथ्य से प्रभावित है, और चाहे वह उससे पहले का हो या उसके बाद का। आरएम मलकानी बनाम महाराष्ट्र राज्य, एआईआर 1973 एससी 157 में इस अदालत ने यह स्पष्ट कर दिया कि इलेक्ट्रॉनिक रूप से रिकॉर्ड की गई बातचीत साक्ष्य में स्वीकार्य है, यदि बातचीत संबंधित मामले से संबंधित है और आवाज की पहचान की गई है और रिकॉर्ड की गई बातचीत की सटीकता सही है। 'मिटाने, जोड़ने या हेरफेर की संभावना को समाप्त करके सिद्ध किया गया। इस न्यायालय ने आगे कहा कि किसी प्रासंगिक बातचीत की समसामयिक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डिंग एक प्रासंगिक घटना की तस्वीर के बराबर एक प्रासंगिक तथ्य है और अधिनियम की धारा 8 के तहत साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य है। इसलिए इसमें कोई संदेह नहीं है कि ऐसे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को साक्ष्य के रूप में प्राप्त किया जा सकता है। "

(33) विचाराधीन मुद्दे पर केके वेलुसामी के मामले (सुप्रा), नवजोत संधू के मामले (सुप्रा), राम सिंह के मामले (सुप्रा) आदि जैसे विभिन्न मामलों में पहले ही विचार किया जा चुका है कि यदि रिकॉर्ड किया गया संस्करण पर्याप्त है और बयान साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया गया है। , यह साक्ष्य में प्रासंगिक और स्वीकार्य है, बशर्ते ऐसी रिकॉर्डिंग के साथ छेड़छाड़ न की गई हो और आवाज की उचित पहचान की गई हो।

(34) प्रथम लोक उच्चतम न्यायालय ने विकास कुमार रूड़कीवाल बनाम राज्य ओज उत्तराखंड (11) में कहा है:

“22. यानी निष्पक्ष सुनवाई की आवश्यकता पर शायद ही जोर देने की जरूरत है। गवाहों की सुरक्षा में, कम से कम संवेदनशील मामलों में रुकावट डालने में, स्लेट की एक निश्चित भूमिका है। विद्वान न्यायाधीश मुकदमे में सहभागी भूमिका निभाने में विफल रहे हैं। 1 यानी गवाहों द्वारा जो कुछ भी कहा गया है उसे रिकॉर्ड करने के लिए महज एक टेप रिकॉर्डर की तरह काम करने की उम्मीद नहीं की गई थी। संहिता की धारा 311 और साक्ष्य अधिनियम की धारा 165 न्यायालय को साक्ष्य एकत्र करने की प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभाकर सभी आवश्यक सामग्री प्राप्त करने की विशाल और व्यापक शक्तियाँ प्रदान करती है। रिकॉर्ड यह नहीं दर्शाता है कि मुकदमे की अध्यक्षता करने वाले विद्वान न्यायाधीश ने साक्ष्य अधिनियम की धारा 165 के तहत शक्तियों का प्रयोग किया था जो एक तरह से उनकी अन्य शक्तियों की पूरक है।" भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 165 इस प्रकार है:

“165. प्रश्न पूछने या उत्पादन का आदेश देने की न्यायाधीश की शक्ति.-

न्यायाधीश, प्रासंगिक तथ्यों की खोज करने या उनका उचित प्रमाण प्राप्त करने के लिए, किसी भी समय, किसी भी रूप में, किसी भी गवाह से, या पार्टियों से किसी भी प्रासंगिक या अप्रासंगिक तथ्य के बारे में कोई भी प्रश्न पूछ सकता है; और किसी दस्तावेज़ या चीज़ के उत्पादन का आदेश दे सकता है; और न ही पार्टियाँ और न ही उनके एजेंट कोई आपत्ति करने के हकदार होंगे

ऐसा कोई भी प्रश्न या आदेश, न ही, ऐसे किसी भी प्रश्न के उत्तर में दिए गए किसी भी उत्तर पर किसी भी गवाह से जिरह करने के लिए न्यायालय की अनुमति के बिना:

बशर्ते कि निर्णय इस अधिनियम द्वारा प्रासंगिक घोषित किए गए तथ्यों पर आधारित होना चाहिए, और विधिवत साबित होना चाहिए।

बशर्ते कि यह धारा किसी भी न्यायाधीश को किसी भी गवाह को किसी भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए बाध्य करने या कोई दस्तावेज तैयार करने के लिए अधिकृत नहीं करेगी, जिसे ऐसा गवाह धारा 121 से 131 के तहत जवाब देने या पेश करने से इनकार करने का हकदार होगा, दोनों शामिल हैं, यदि प्रश्न पूछे गए थे या विरोधी पक्ष द्वारा दस्तावेज़ मांगे गए थे; न ही न्यायाधीश कोई ऐसा प्रश्न पूछेगा जिसे धारा 148 या 149 के तहत पूछना किसी अन्य व्यक्ति के लिए अनुचित होगा; न ही वह यहां पहले छोड़े गए मामलों को छोड़कर, किसी दस्तावेज़ के प्राथमिक साक्ष्य से छूट देगा?'

(35) 'इस अनुभाग का उद्देश्य सच्चाई तक पहुंचने के उद्देश्य से न्यायाधीश को सबसे

व्यापक शक्ति प्रदान करना है। इस धारा का प्रभाव यह है कि अपने समक्ष मामले की तह तक जाने के लिए न्यायालय को अपने समक्ष उपस्थित प्रत्येक तथ्य को देखना और जांच करना पड़ता है। मैं न्यायाधीश की इस व्यापक शक्ति का अपवाद हूं कि गवाह को किसी भी प्रश्न का उत्तर देने या धारा 121 से 131 साक्ष्य अधिनियम के विपरीत कोई दस्तावेज़ या धारा 148 या 149, साक्ष्य अधिनियम के विपरीत कोई भी प्रश्न प्रस्तुत करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है और न्यायाधीश ऐसा नहीं करेगा। अधिनियम में दिए गए प्रावधानों को छोड़कर किसी भी दस्तावेज़ के प्राथमिक साक्ष्य से छूट।

(36) ***जाहिरा हुहिहुल्ला आईएल शेख और अन्य बनाम गुजरात राज्य और अन्य (12) मामले में आई लोन्ब्लक सुप्रीम कोर्ट ने निम्नानुसार टिप्पणी की:***

> "43. अदालतों को मुकदमे में सहभागी भूमिका निभानी होगी। उनसे यह अपेक्षा नहीं की जाती है कि वे टेप रिकॉर्डर हों और गवाहों द्वारा जो कुछ भी कहा जा रहा है उसे रिकॉर्ड कर सकें। संहिता की धारा 311 और साक्ष्य अधिनियम की धारा 165 न्यायालय के पीठासीन अधिकारियों को साक्ष्य एकत्र करने की प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभाकर सभी आवश्यक सामग्री प्राप्त करने की विशाल और व्यापक शक्तियाँ प्रदान करती हैं। उन्हें कार्यवाही की निगरानी करनी होगीन्याय की सहायता के लिए इस तरीके से कि जो चीज़ प्रासंगिक नहीं है, उसे अनावश्यक रूप से रिकॉर्ड में न लाया जाए। भले ही अभियोजक कुछ मायनों में लापरवाही बरतता है, फिर भी वह कार्यवाही को नियंत्रित कर सकता है ताकि अंतिम उद्देश्य सत्य पर पहुंचा जा सके। यह और भी आवश्यक हो जाता है कि न्यायालय के पास यह विश्वास करने के कारण हों कि अभियोजन एजेंसी या अभियोजक अपेक्षित तरीके से कार्य नहीं कर रहा है। 'न्यायालय ऐसे गंभीर नुकसानों या अभियोजन एजेंसी की ओर से कर्तव्य की उपेक्षा के प्रति इच्छापूर्वक या आनंदपूर्वक अनभिज्ञ होने या अनजान होने का दिखावा नहीं कर सकता। अभियोजक जो निष्पक्षता से कार्य नहीं करता है और बचाव के लिए एक वकील की तरह कार्य करता है, वह निष्पक्ष न्यायिक प्रणाली के लिए एक दायित्व है, और अदालतें ऐसी अभियोजन एजेंसी के हाथों में नहीं खेल सकती हैं जो गलतियाँ दिखा रही हैं या पूर्ण अलगाव का रवैया अपना रही हैं।

(44) साक्ष्य अधिनियम की धारा 165 के तहत न्यायालय की शक्ति एक तरह से संहिता की धारा 311 के तहत उसकी शक्ति की पूरक है। इस धारा में दो भाग हैं (i) न्यायालय को किसी भी स्तर पर गवाह की जांच करने का विवेक देना और (ii) अनिवार्य नियम जो अदालतों को किसी गवाह की जांच करने के लिए मजबूर करता है यदि उसका साक्ष्य न्यायपूर्ण निर्णय के लिए आवश्यक प्रतीत होता है। कोर्ट। हालाँकि न्यायालय को दिया गया विवेकाधिकार बहुत व्यापक है, लेकिन उसी चौड़ाई के लिए समान सावधानी की आवश्यकता होती है। मोहन लाल बनाम भारत

संघ में, इस न्यायालय ने धारा 311 के दायरे और दायरे पर विचार करते हुए देखा है कि, "किसी भी न्यायालय" "किसी भी स्तर पर", या "किसी भी जांच या परीक्षण या" जैसे शब्द का उपयोग अन्य कार्यवाही" "कोई भी व्यक्ति" और "ऐसा कोई भी व्यक्ति" स्पष्ट रूप से बताता है कि धारा ने व्यापक संभव शब्दों में व्यक्त किया है और किसी भी तरह से न्यायालय के विवेक को सीमित नहीं करता है। हालाँकि, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, बहुत चौड़ाई में एक समान सावधानी की आवश्यकता होती है कि विवेकाधीन शक्तियों को न्याय की आवश्यकताओं के अनुसार लागू किया जाना चाहिए और सावधानी के साथ और संहिता के प्रावधानों के अनुरूप न्यायिक रूप से प्रयोग किया जाना चाहिए। धारा का दूसरा भाग किसी भी विवेक की अनुमति नहीं देता है, लेकिन अदालत को आवश्यक कदम उठाने के लिए बाध्य और बाध्य करता है यदि प्राप्त किए जाने वाले नए साक्ष्य मामले के उचित निर्णय के लिए आवश्यक हैं - एक सक्रिय और सतर्क दिमाग के लिए 'आवश्यक' और उसे नहीं जो मुड़ा हुआ है

त्यागना या छोड़ देना। धारा का उद्देश्य अदालत को इस तथ्य के बावजूद सच्चाई तक पहुंचने में सक्षम बनाना है कि अभियोजन या बचाव पक्ष कुछ सबूत पेश करने में विफल रहा है जो मामले के उचित और उचित निपटान के लिए आवश्यक है। शक्ति का प्रयोग किया जाता है और सबूतों की जांच न तो अभियोजन और न ही बचाव में मदद के लिए की जाती है, मुझे लगता है कि धारा 3 11 के संदर्भ में कार्य करने की आवश्यकता है, बल्कि केवल न्याय और सार्वजनिक हित की पूर्ति के लिए। यह उचित निर्णय की सहायता के लिए साक्ष्य प्राप्त करने और सत्य को बरकरार रखने के उद्देश्य से किया जाता है।

(45) ऐसा नहीं है कि हर मामले में जहां अदालत के समक्ष गवाही देने वाला गवाह अपना मन बदलना चाहता है और अलग तरह से बोलने के लिए तैयार है, संबंधित अदालत को अपनी सहायता देकर ऐसे अनुरोध को तुरंत स्वीकार करना चाहिए। यदि गवाह, जिसने पहले एक तरह से गवाही दी थी, अपीलीय न्यायालय के समक्ष इस प्रार्थना के साथ आता है कि वह ऐसे साक्ष्य देने के लिए तैयार है जो पहले की चूक के कारणों के साथ मुकदमे में उसके द्वारा पहले दिए गए साक्ष्य से भिन्न है, तो न्यायालय इस पर विचार कर सकता है। प्रार्थना की वास्तविकता इस संदर्भ में है कि क्या संबंधित पक्ष को पहले सच बोलने और उचित मामले में इसे स्वीकार करने का उचित अवसर मिला था। ऐसा नहीं है कि शक्ति का प्रयोग नियमित तरीके से किया जाना है, बल्कि असाधारण आसानी या असाधारण स्थिति में प्राप्त रिकॉर्ड के आधार पर अपील के निपटान के सामान्य नियम का अपवाद होने के कारण न्यायालय न तो शक्तिहीन महसूस कर सकता है और न ही अपने कर्तव्य से विमुख हो सकता है। सत्य तक पहुंचें और केवल बर्फ के सिरे को संतुष्ट करें। 'मैं न्यायालय को निश्चित रूप से रूपक द्वारा निर्देशित कर सकता हूं, अनाज को भूसी से अलग कर सकता हूं, और जिस सहजता से प्रार्थना में तर्कसंगतता और वास्तविकता की स्पष्ट छाप होती है, उसे स्वीकार करना होगा, कम से कम मूल्य,

> विश्वसनीयता पर विचार करना होगा और लाई जाने वाली सामग्री के गुण-दोष के आधार पर उसकी स्वीकार्यता।"

(37) उपरोक्त के आलोक में, वर्तमान मामले में, दोषी/अभियुक्त के पास निष्पक्ष सुनवाई और अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए समान अवसर का अपरिहार्य अधिकार है। यह स्थापित कानून है कि बचाव साक्ष्य पेश करने का आरोपी का अधिकार न केवल एक औपचारिकता है, बल्कि आपराधिक मुकदमे का एक अनिवार्य हिस्सा है, जहां हर अवसर आवश्यक है और यह आरोपी को अपनी बेगुनाही साबित करने और बचाव पेश करने के लिए दिया जाना चाहिए।

(38) कल्याणी इलास्कर (श्रीमती) बनाम एमएस संपूर्णम (श्रीमती) (13) के मामले में प्रथम उच्चतम न्यायालय ने निम्नानुसार व्यवस्था दी है:-

> "12.../आई11सी अपीलकर्ता को उसके साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिए बिना दोषी नहीं ठहराया जा सकता है और मुझे लगता है कि उसे इससे वंचित कर दिया गया है, कोई निष्पक्ष सुनवाई नहीं है, "एल-'एयर ट्रायल" में निष्पक्ष और उचित अवसर शामिल हैं उसकी बेगुनाही साबित करने के लिए कानून। बचाव के समर्थन में सबूत पेश करना एक मूल्यवान अधिकार है। उस अधिकार से इनकार का मतलब निष्पक्ष सुनवाई से इनकार है। यह आवश्यक है कि न्याय सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई प्रक्रिया के नियमों का ईमानदारी से पालन किया जाना चाहिए, और अदालतों को यह देखने में ईर्ष्या होनी चाहिए कि उनका कोई उल्लंघन न हो...।"

(39) मौजूदा मामले में, उपरोक्त तीन याचिकाओं में याचिकाकर्ता ने तीन अलग-अलग आवेदन दिए हैं, एक पीड़िता की दोबारा जांच के लिए, दूसरा पीड़िता की आवाज का नमूना लेने और इस मामले में अपनी बेगुनाही और झूठे निहितार्थ को साबित करने के लिए उनकी तुलना करने के लिए। ऐसा करके याचिकाकर्ता बातचीत और बातचीत की प्रतिलेखों को साबित कर सकता है जो कानून के अनुसार प्रासंगिक और स्वीकार्य साक्ष्य हैं, बशर्ते कि वे विभिन्न निर्णयों में आई लोन्ब्लक सुप्रीम कोर्ट द्वारा उल्लिखित शर्तों की संतुष्टि के अधीन हों।

(40) उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, मेरी राय में, याचिकाकर्ता को अपनी बेगुनाही साबित करने का अवसर देना उचित और निष्पक्ष होगा।

(41) परिणामस्वरूप, उपरोक्त सभी तीन आपराधिक पुनरीक्षण याचिकाएँ स्वीकार की जाती हैं। नतीजतन, याचिकाकर्ता द्वारा पीड़िता की दोबारा जांच करने, आवाज का नमूना लेने और सीडी के साथ पीड़िता की आवाज का नमूना प्रयोगशाला में भेजने के लिए याचिकाकर्ता द्वारा दिए गए सभी तीन आवेदन स्वीकार कर लिए गए और दिनांक 16.01.2013 के विवादित आदेश विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, कैथल द्वारा पारित किए गए मामले को खारिज कर दिया। ट्रायल

कोर्ट को निर्देश दिया गया है कि अभियोजक से केवल सेल फोन पर रिकॉर्ड की गई बातचीत के संबंध में पूछताछ की जाए और उसकी आवाज का नमूना लिया जाए और उसे वैज्ञानिक विश्लेषण के लिए भेजा जाए।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

ममता,
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
रोहतक, हरियाणा।